

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2942/2024

शपत खान

—अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, कार्मिक, शासन सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2024

आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री महिपाल खर्रा मार्फत श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष:- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जायें कि अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के विरुद्ध वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत नहीं किया गया था। परंतु उसे वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को दी गई तिथि से पदोन्नति एवं समस्त लाभ प्रदान किये जावें।
3. अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं—
4. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पुलिस उप अधीक्षक के पद पर सहायक कमान्डेंट 14वीं बटालियन आरएसी पहाडी में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.05.1991 के द्वारा उप निरीक्षक के पद पर हुई थी। तत्पश्चात् दिनांक 01.05.2017 को अपीलार्थी को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा

राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.03.2023 (अनुलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26.07.2022 को दिये गये ज्ञापन में परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त दण्ड के विरुद्ध दिनांक 26.06.2023 (अनुलग्नक-4) के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 3 के यहां अपील दायर की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2018 (अनुलग्नक-5) के द्वारा वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध अपीलार्थी को दिनांक 01.06.2017 से कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर है एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को क्रम संख्या 20, 23, 26, 27, 28 एवं 29 पर अंकित है। आदेश दिनांक 18.04.2023 (अनुलग्नक-6) के द्वारा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 39 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.01.2024 की अभिशंषानुसार अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2022 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने पर अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया।

5. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2024 (अनुलग्नक-7) के द्वारा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2024 की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों का नाम सम्मिलित किया गया। वरिष्ठ वेतन श्रृंखला अर्थात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर अगले वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का नाम जोन ऑफ कन्सीडरेशन में नहीं आने पर पदोन्नति नहीं हो सकेगी।
6. उनका कथन है कि परिनिन्दा का दण्ड लघु दण्ड की परिभाषा में आता है और सीसीए नियम 17 के अंतर्गत उक्त दण्ड दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लघु दण्ड के आधार पर व परिनिन्दा दण्ड के आधार पर कर्मचारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति से ऐसे मामले में वंचित नहीं किया जा सकता। परन्तु अपीलार्थी को परिनिन्दा के दण्ड के

आधार पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है:—

44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can safely held that the Circular dated 04-06-2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.

45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30-05-2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27-12-2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated 26-10-2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04-06-2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, are quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.

46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today."

7. इसी प्रकार अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 2153/2004 विजय कृष्ण व्यास बनाम आयुक्त, आबकारी विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5715/1997 हरभजन मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2010 जिसमें याची के याचिका को स्वीकार कर हकदार माना है। इसी प्रकार अपीलार्थी भी उपरोक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति से वंचित रखा गया है।
8. अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 2023–24 के विरुद्ध पदोन्नत किया जावे और जिस आदेश दिनांक 29.01.2024 के द्वारा कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है। उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति देते हुये समस्त लाभ प्रदान किये जायें।
9. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता के द्वारा अपील में जवाब में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।
11. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.05.1991 के द्वारा उपनिरीक्षक के पद पर हुई थी। तत्पश्चात् दिनांक 01.05.2017 को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.03.2023 (अनुलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26.07.2022 को दिये गये ज्ञापन राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-17 में परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त दण्ड के विरुद्ध दिनांक 21.03.2023 (अनुलग्नक-4) के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 3 के यहां अपील दायर की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2018 (अनुलग्नक-5) के द्वारा वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध अपीलार्थी को दिनांक 01.06.2017 से कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर है एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को क्रम संख्या 20, 23, 26, 27, 28 एवं 29 पर अंकित है। आदेश दिनांक 18.04.2023 (अनुलग्नक-6) के द्वारा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 39 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.01.2024 की अभिशंषानुसार अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत कर दिया गया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2022 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने पर अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2024 (अनुलग्नक-7) के द्वारा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2024 की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों का नाम सम्मिलित किया गया। वरिष्ठ वेतन श्रृंखला अर्थात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर अगले वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का नाम जोन ऑफ कन्सीडरेशन में नहीं आने पर पदोन्नति नहीं हो सकेगी। परिनिन्दा का दण्ड लघु दण्ड की परिभाषा में आता है और सीसीए नियम 17 के अंतर्गत उक्त दण्ड दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह

सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लघु दण्ड परिनिंदा दण्ड के आधार पर कर्मचारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के ऐसे मामले में वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड के आधार पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है:-

44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can safely held that the Circular dated 04-06-2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.

45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30-05-2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27-12-2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated 26-10-2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04-06-2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, are quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.

46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today."

13. इसी प्रकार अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 2153/2004 विजय कृष्ण व्यास बनाम आयुक्त, आबकारी विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5715/1997 हरभजन मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2010 जिसमें याची के याचिका को स्वीकार कर हकदार माना है। इसी प्रकार अपीलार्थी भी उपरोक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति से वंचित रखा गया है और उक्त प्रकरण में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है :-

"In view of what has been discussed above, action of the Respondents/DPC- in judging the petitioner not suitable for promotion solely on the ground that he was awarded penalty of censure, despite criteria of promotion being seniority-cum-merit, cannot be said to be legal and justified because for considering the case for promotion on the criteria of seniority-cum-merit for promotion. what is to be seen is

the minimum necessary merit requisite for efficiency of administration and the senior even though less meritorious. shall have primacy in the matter of promotion and comparative assessment of merit is not required to be made.

In the result, this writ petition deserves to be partly allowed and it is accordingly partly allowed. The petitioner is held entitled to promotion against the vacancy of the year 1995-96, if this juniors were promoted on the criteria of seniority-cum-merit from such date. The petitioner shall also be entitled to get all the consequential benefits with interest at the rate of 6% per annum."

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाती है तथा उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2023-24 के विरुद्ध वरिष्ठ वेतन श्रृंखला (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) के पद पर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर रिक्ति वर्ष 2023-24 हेतु विचार किया जावे और पदोन्नति के लिए पात्र पाया जाता है तो उसे भी पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जायें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष